तक पहुंचाना चाहिए। उनकी अन्य समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना चाहिए।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उम्मीद बनी रहे, इसके लिए रोजगार कार्य आरंभ करने के साथ समय पर उचित मजदूरी का भुगतान करना भी बहुत जरूरी है। मानिकपुर प्रखंड में एक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने बताया कि इस क्षेत्र में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां कई महीने पहले मनरेगा का कार्य करने वाले मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं मिली है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तो ऐसा अन्याय कभी नहीं होना चाहिए कि देर तक मजदूरी ही न मिले।

इन कार्यों के अन्तर्गत जल व मिट्टी संरक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य करने की बड़ी संभावनाएं हैं जिससे आगे चलकर किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में व कम वर्षा के समय में भी अपनी खेती–किसानी की रक्षा में बहुत मदद मिलेगी। विशेषकर खेत तालाब बनाने का कार्य काफी उपयोगी रहा है। एक सवाल सामने है कि क्या मनरेगा व सूखा–राहत के बजट का सही उपयोग इस तरह हो सकेगा कि वास्तव में मिट्टी व जल संरक्षण की बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो ?

चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र में वाटरशेड परियोजनाओं में कार्य भलीभांति तकनीकी कुशलताओं के किया गया है, वहां कुछ गांवों में दिसंबर महीने में भी तालाबों में सिंचाई के लिए व पशुओं से पीने के लिए पानी उपलब्ध था। मनगवां के किसान कोदू कोल ने मुस्कराते हुए कहा, "इस पानी का उपयोग कर मैं इस वर्ष भी परिवार के लिए पर्याप्त अनाज अपने खेत से प्राप्त कर सकता हूँ।"

इन वाटरशेड कार्यों को अखिल भारतीय समाजसेवा संस्थान ने कार्यान्वित किया। इस संस्थान के निदेशक भागवत प्रसाद बताते हैं, "हमारा यह प्रयास रहा कि बाहरी तकनीकी कुशलता व सुझाव तो जरूरत पड़ने पर प्राप्त किए जाएं, पर साथ में स्थानीय आदिवासियों व अन्य किसानों व उनकी स्थानीय समितियों के नजदीकी सहयोग से ही कार्य किया जाए। तभी यह कार्य उनकी खेती–किसानी को बेहतर करने में सफल होगा।"

भागवत प्रसाद यहां व टीकमगढ़ जिले में जैविक खेती के प्रयोगों से भी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह जहां एक ओर किसानों का खर्च कम हुआ, वहां उनका उत्पादन व आय बढ़ाने में सहायता मिली।

जालौन जिले में जनकल्याण संस्था के कार्यक्षेत्र में भी जैविक कार्य की अच्छी सफ़लता नजर आई है वह भी महिला किसानों की उत्साहवर्धक भागेदारी से। यहां व कानपुर जिले के कुछ प्रयासों से स्पष्ट होता है कि जैविक खेती के प्रसार से महिलाओं की विशेष रुचि है क्योंकि इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। खर्चीली व बाहरी निवेश निर्भर खेती के स्थान पर महिला किसान आत्मनिर्भरता की खेती करना चाहती हैं फिर चाहे इसके लिए उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़े।

इस समय तो तुरंत राहत पंहुचाने की जरूरत है पर दीर्घकालीन स्तर पर देखें तो जल व मिट्टी संरक्षण तथा जैविक खेती से खेती–किसानी को बहुत राहत मिल सकती हे तथा इस ओर समुचित ध्यान देना बहुत जरूरी है।

सूखे व अन्य तरह के प्रतिकूल मौसम का संकट इस जलवायु बदलाव के दौर में किसानों के लिए बढ़ता जा रहा है। अतः सरकारों को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि वे किसानों के हित से जुड़े कार्यक्रमों व आपदा प्रबंधन के लिए आगामी वर्षों में अधिक संसाधन उपलब्ध करवाएंगी। इसके अतिरिक्त शहरी लोगों को भी गांवों व विशेषकर किसानों की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा सूखे से त्रस्त किसानों की सहायता के लिए आपसी सहयोग से प्रयास होना चाहिए। (सप्रेस)

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि 'सर्वोदय प्रेस समिति' के नाम भेजें।